'एम-पैक्स सदस्यता महाअभियान–2025' का शुभारम्भ

दिनांक- 12-09-2025

मुख्य अतिथि
मा० केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन श्री मुरलीधर मोहोल जी

स्थान
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (आईजीपी), लखनऊ

उद्देश्य
IYC-2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने का संकल्प

मा० अतिथिगण एवं प्रतिभागी

- मा० मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग उ०प्र०, **श्री धर्मपाल सिंह जी**
- मा० मंत्री मत्स्य पालन विभाग उ०प्र०, **श्री संजय निषाद जी**
- मा० राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता विभाग उ०प्र०, **श्री जे०पी०एस० राठौर जी**
- जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षगण
- विभागीय अधिकारीगण
- प्रदेश के विभिन्न जिलों के कोऑपरेटर्स

छायाचित्र:-

छायाचित्र:-

छायाचित्र:-

Five Lakh only
₹ 5,00,000.00

एम–पैक्स सदस्यता महा अभियान 2025
दिनांक 12 सितम्बर, 2025

छायाचित्र:-

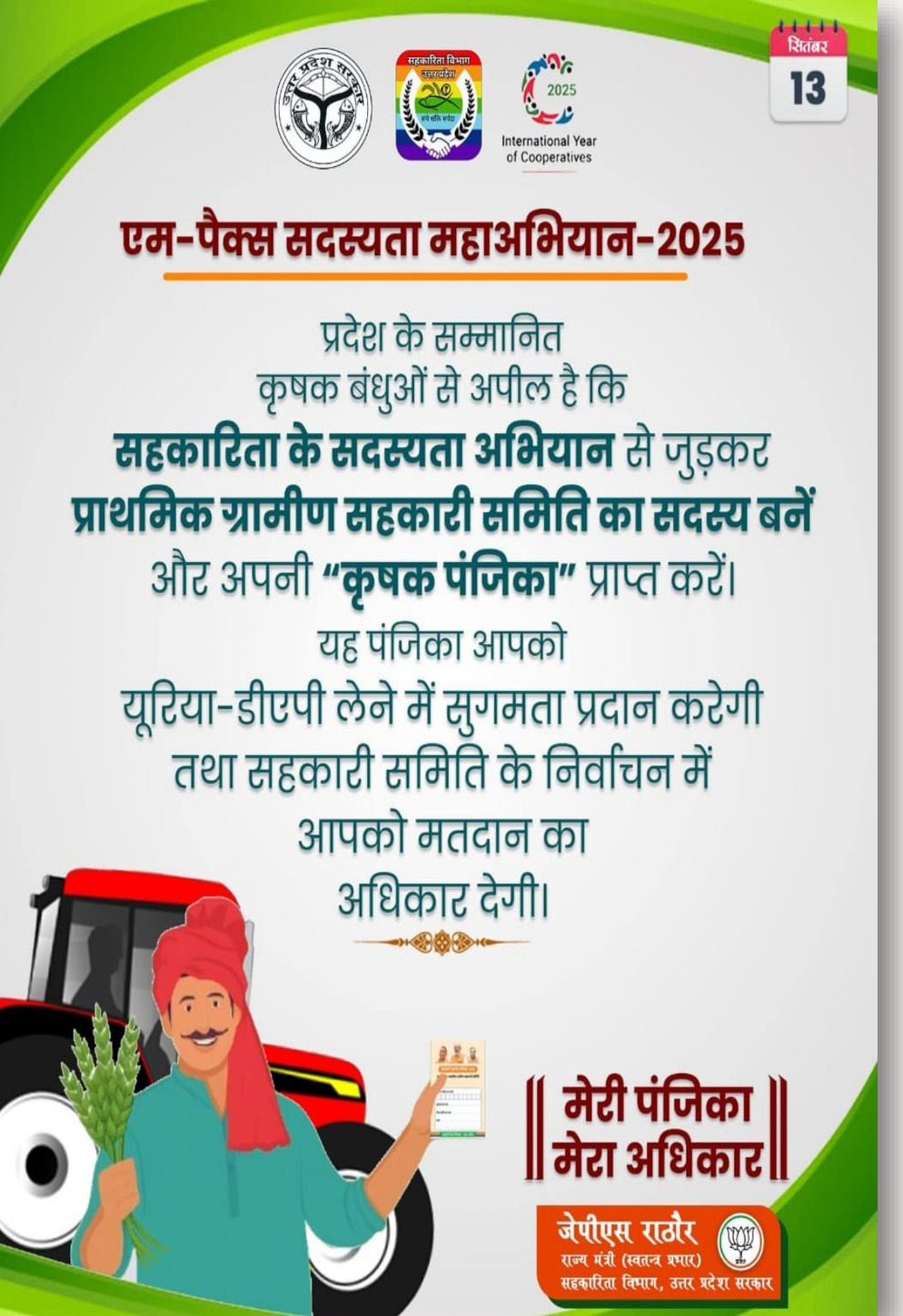

International Year of Cooperatives

Cooperatives Build a Better World

मेरी पंजिका, मेरा अधिकार

एम-पैक्स सदस्यता

महाअभियान-2025 के माध्यम से अपने अधिकारों को सुनिश्चित करें

प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति

समुदाय के साथ जुड़कर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाएं

सदस्यता के लाभ

- वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच
- कृषि ऋण और सब्सिडी की सुविधा
- सामुदायिक विकास में भागीदारी
- आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता

अभी जुड़ें!

एम-पैक्स महाअभियान-2025 के तहत अपनी सदस्यता सुनिश्चित करें और ग्रामीण विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बनें।

2025
International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

सहकारिता विभाग
उत्तर प्रदेश
संघे शक्ति सर्वदा

"साथ आयें-सहकारिता का भाव जगायें"

केवल ₹100 जमा करें
न्यूनतम राशि में अपना बचत खाता खुलवाएं

जिला सहकारी बैंक
विश्वसनीय और सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं

सस्ती दरों पर ऋण
फसली ऋण और अन्य बैंकिंग सुविधाएं

सम्मानित कृषक बंधुओं

सदस्यता अभियान की अवधि में यह सुनहरा अवसर प्राप्त करें।
सहकारिता के माध्यम से अपनी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करें और
समुदाय के साथ मिलकर प्रगति करें।

अभी शामिल हों और लाभ उठाएं!
यह सीमित समय का प्रस्ताव है - आज ही अपना सदस्यता फॉर्म भरें।

मीडिया गैलरी :-

एम पैक्स के 24 लाख नये सदस्य बनाये जाएंगे : राठौर

एम-पैक्स सदस्यता महाअभियान शुरू, केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री ने किया शुभारम्भ

लखनऊ (एसएनबी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने एवं किसानों के हित में सहकारिता आन्दोलन को सशक्त बनाने के लिए राज्य की सभी एम-पैक्स (बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां) में एक माह तक चलने वाले सदस्यता महाअभियान का इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में शुभारम्भ किया। अभियान का शुभारंभ सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भारत सरकार मुरलीधर मोहोल ने किया।

इस अवसर पर श्री मोहोल ने कहा कि भारत सरकार के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में अब तक कई महत्वपूर्ण पहलें हुई हैं। पैक्स को बहुउद्देश्यीय संस्थान के रूप में विकसित करने, 2 लाख नए पैक्स गठित करने तथा महिलाओं एवं वंचित वर्ग के प्रतिनिधित्व को अनिवार्यकरने जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद से पैक्स कम्प्यूटरीकरण, किसान समृद्धि केन्द्र, भण्डारण क्षमता विस्तार और ब्याजमुक्त ऋण जैसी योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। एक माह में 30 लाख नए सदस्य जोड़ना इसका प्रमाण है।

प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने कहा कि सदस्यता महाअभियान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने एवं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा

एम पैक्स सबस्यों को मिलेगा यूनिक आईडी

में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रत्येक किसान को सहकारिता से जोड़ना ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहली बार 2023 में एम-पैक्स सदस्यता महाअभियान का शुभारम्भ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। इस अभियान में लगभग 30 लाख नए सदस्य जुड़े एवं 70 करोड़ रुपये अंशधन (शेयर कैपिटल) प्राप्त हुआ। इस सहकारिता जनआन्दोलन से प्रदेश में नई ऊर्जा का संचार हुआ, जो दर्शाता है कि वर्तमान में सहकारिता नागरिकों के विश्वास का आधार बन चुकी है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की 6900 एम-पैक्स को उर्वरक व्यवसाय के लिए 10 लाख रु पये की ब्याजमुक्त कैश क्रेडिट लिमिट से वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे लगभग 5400 करोड़ रु पये का व्यवसाय हुआ और 120 करोड़ रुपये की आय एम-पैक्स को हुई। इस ऋण सीमा को 15 लाख रु पये तक बढ़ाकर व्यवसाय में विविधीकरण किया जाना प्रस्तावित है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सदस्यों को नैनी यूरिया, उर्वरक, उन्नत बीज/बीज उत्पादन, कृषि मशीनरी/यंत्रीकरण, कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं अन्य उत्पादन सम्बन्धी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। एम-पैक्स के सदस्यों को यूनिक आईडी प्राप्त होगी तथा सभी गैर सदस्यों को एम-पैक्स का सदस्य बनाकर लाभान्वित किया जायेगा।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित "सोलर रूफटॉप विद्युतीकरण योजना" के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में 258 एम-पैक्स पर 5 करोड़ रुपये की लागत से सोलर पैनल लगाये गये। वर्ष 2025-26 में 300 समितियों में सोलर रूफटॉप लगाए जाने का प्रस्ताव है। सहकारी समितियों के पुराने एवं जर्जर गोदामों की मरम्मत हेतु प्रत्येक एम-पैक्स को 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी गई है। ड्रोन पायलट प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत गत वर्ष 266 "ड्रोन दीदियों" को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाया गया। इस अवसर पर मंत्री धर्मपाल सिंह , संजय कुमार निषाद, वैभव श्रीवास्तव प्रबन्ध निदेशक पीसीडीएफ, अनिल कुमार सिंह अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक सहकारिता, आर के कुलश्रेष्ठ प्रबन्ध निदेशक कोऑपरेटिव बैंक, श्रीकान्त गोस्वामी अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक सहकारिता, आर डी गुप्ता प्रबंध निदेशक राज्य भंडारण निगम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

एम-पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने से हर वर्ग को फायदा : मुरलीधर

केंद्रीय राज्यमंत्री ने एम-पैक्स सदस्यता महाअभियान की शुरुआत की

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एम-पैक्स) को बहुउद्देशीय संस्थान के रूप में विकसित करने का प्रयास चल रहा है। दो लाख नए पैक्स गठित करने तथा महिलाओं एवं वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश है। वह शुक्रवार को सहकारिता विभाग की ओर से लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एम-पैक्स सदस्यता महाअभियान 2025 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की एम-पैक्स किसानों के साथ-साथ जनसामान्य पर भी अपनी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली की छाप छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि एक माह में 30 लाख नए सदस्य जोड़ना इसका प्रमाण है। प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने कहा कि जो समितियां पहले भ्रष्टाचार का अड्डा थीं वो अब किसानों के लिए हितैषी साबित हो रही हैं। पहले 50 में से 16 सहकारी बैंकों के व्यवसाय करने पर रोक लगी थी। वे बंदी के कगार

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुक्रवार को केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने एम-पैक्स सदस्यता महाभियान की शुरुआत की। इससे पहले प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री जेपीएस राठौर समेत अन्य मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। -संवाद

सहकारिता राज्यमंत्री बोले- घाटे में रहने वाली समितियां अब कमा रहीं मुनाफा

पर थे। अब वे लाभ में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इटावा के सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदित्य यादव हैं। वह घाटे में हैं। प्रदेश की समितियां इस वर्ष करीब 120 करोड़ का मुनाफा कमा चुकी हैं। यूपी में 715 नई समितियां गठित हुई हैं।

मत्स्य विकास मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा कि समितियों ने किसानों और युवाओं को नई पहचान दी है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी

इस तरह ले सकते हैं सदस्यता

सहकारिता मंत्री ने कहा कि सदस्य बनने के लिए निकटतम एम-पैक्स अथवा जिला सहकारी बैंक/शाखा से संपर्क किया जा सकता है। टोल फ्री नंबर 18002128444 पर कॉल कर अपना जनपद, विकास खंड व गांव का नाम दर्ज कराएं। ऑनलाइन आवेदन के लिए www.pacsmember.in पर जाकर अपना नाम व मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं।

केवल खेती से नहीं बल्कि पशुपालन को बढ़ावा देकर ही पूरी होगी। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली समितियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

अनाज भंडारण के लिए नए गोदामों का जनवरी से शुरू होगा निर्माण

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनाज भंडारण के लिए गोदाम निर्माण किसानों की समृद्धि का आधार है, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के साथ सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दिए। अनाज भंडारण योजना की प्रगति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि एफसीआई ने प्रदेश के 35 जनपदों में 96 स्थलों की पहचान की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 15 नवंबर 2025 तक वित्तीय समापन प्रक्रिया पूरी कर जनवरी 2026 से निर्माण कार्य प्रारंभ कर अप्रैल 2026 तक काम पूरा कर लिया जाए। एम-पैक्स के गठन पर चर्चा के दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 2024-25 में 266 एम-पैक्स के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 457 नये एम-पैक्स गठित हो चुके हैं। सितंबर में 1088 ग्राम पंचायतों में संगठन की प्रक्रिया चल रही है। एम-पैक्स को उर्वरक वितरण के लिए 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण सीमा दी गई है, जिससे अब तक 5400 करोड़ का टर्नओवर और 120 करोड़ की मार्जिन मनी प्राप्त हुई है। ब्यूरो

'यूपी की सहकारिता योजनाओं को दूसरे राज्यों में ले जाएंगे'

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि अगले पांच सालों में देश की सभी ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (एम-पैक्स) होंगी। इसके लिए पांच सालों में दो लाख नए एम-पैक्स गठन का लक्ष्य लेकर सहकारिता मंत्रालय काम कर रहा है। यूपी इस काम में आगे है, यहां अब तक 715 नए एम-पैक्स का गठन हो चुका है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर शुक्रवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एम-पैक्स के सदस्यता महाअभियान की शुरुआत की। मुरलीधर ने प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह, मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के साथ सदस्यता अभियान और उसके नवीन डिजिटल पोर्टल को शुरू किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपी में जिस तरह पैक्स को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए दो-दो लाख रुपये की आर्थिक मदद राज्य सरकार की ओर से दी गई है, यह सीएम योगी की सहकारिता के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वह यूपी की इन नई योजनाओं को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने का काम करेंगे। यूपी में जिला सहकारी बैंक (डीसीबी) की 50 शाखाएं हैं, इतनी शाखाएं किसी राज्य में नहीं हैं। डीसीबी को मजबूत करने के लिए ही केंद्रीय सहकारिता मंत्री

> केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने की एम-पैक्स सदस्यता अभियान की शुरुआत

केंद्रीय मंत्री ने कई लोगों को सम्मानित किया

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्र के रूप में सबसे अधिक व्यवसाय करने वाले कोरिहर (रायबरेली) एम-पैक्स के सचिव हरी मोहन सिंह और सभापति वीरेंद्र बहादुर सिंह को, कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में बेहतर काम करने वाले रुस्तमपुर (रायबरेली) एम-पैक्स के सचिव सुनील कुमार और सभापति शत्रोहन लाल को, सर्वाधिक खाद वितरण करने वाले चरथावल (मुजफ्फरनगर) एम-पैक्स की सचिव प्रीति भारद्वाज और सभापति भूषण त्यागी को, सर्वाधिक व्यवसाय करने वाले गोरई (अलीगढ़) एम-पैक्स के सचिव योगेंद्र कुमार और सभापति चंद्रपाल शर्मा को मंच पर सम्मानित किया। साथ ही सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत लखनऊ की बुलबुल जैन और फतेहपुर के आमिर अली को पांच-पांच लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया।

अमित शाह ने 'सहकारिता में सहकार' पर काम शुरू किया है। उन्होंने जेपीएस राठौर से यूपी में भी इस पर काम शुरू करने का अनुरोध किया। आश्वासन दिया कि यूपी में सहकारिता को और मजबूत करने के लिए जो भी सुझाव मिलेंगे, केंद्र सरकार उन पर सकारात्मक विचार करेगी।

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, किसानों की आय दो गुनी सिर्फ खेती से नहीं होगा। किसानों की आय पशुपालन से बढ़ेगी। मत्स्य मंत्री डॉ संजय निषाद ने कहा कि पहले सहकारी समितियां दोहन का साधन थीं, जिन्हें योगी सरकार ने विकास का साधन बना दिया है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा, पहले सहकारिता कुछ लोगों के जेब की संस्था बन कर रह गई थी, जिसे योगी सरकार ने उन लोगों की जेब से निकाल कर जनता की सहकारिता बनाने का काम किया है। पिछली सरकार में यूपी की 16 डीसीबी बंद होने की स्थिति में थी, लेकिन वर्तमान में 50 में से 49 डीसीबी लाभ में है। जो एक शाखा घाटे में है, वहां के अध्यक्ष आदित्य यादव हैं। इस शाखा में पिछले दिनों ₹102 करोड़ का घोटाला भी हो चुका है। पिछली सरकार में यूपी की 7.50 हजार समितियों में से 4,500 समितियां तो बंद हो चुकी थी। योगी सरकार ने उन्हें पुनर्जीवित किया, इसका परिणाम है कि समितियों ने पिछले साल 120 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

उत्तर प्रदेश सरकार

2025
International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

सहकारिता विभाग
उत्तर प्रदेश
संघे शक्ति सर्वदा

धन्यवाद